भारत - कनाडा संबंध

हाल के वर्षों में भारत - कनाडा द्विपक्षीय संबंधों जो लोकतंत्र, बहुलवाद, बढ़ती आर्थिक भागीदारी, उच्च स्तर पर नियमित अंत:क्रिया तथा पुराने जन दर जन संपर्कों पर आधारित है, में बदलाव देखने को मिला है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को एक सामरिक साझेदारी के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए सहमत हुए।

2. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उस समय से चले आ रहे हैं जब भारतीयों ने लघु संख्या में ब्रिटिश कोलंबिया में पलायन करना शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानिक तंत्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। दोनों ही देश जी 20, ए आर एफ, चोगम आदि जैसे अनेक बहुपक्षीय मंचों के सदस्य भी हैं।

3. कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी आई ओ) की संख्या 1.2 मिलियन से अधिक है जो कनाडा की कुल आबादी के 3 प्रतिशत से अधिक है। बहुत अधिक शिक्षित, समृद्ध तथा परिश्रमी पी आई ओ, जो कनाडा में सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है, मुख्य धारा से अच्छी तरह जुड़ा है और दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में काम करते हैं।

4. राजनीतिक स्तर पर हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तर पर अंत:क्रियाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री जीन क्रिस्टीन ने 2003 में और प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन ने 2005 में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री स्टिफन हार्पर ने 15 से 18 नवंबर 2009 के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया जिसके दौरान एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह स्थापित करने के अलावा ऊर्जा सहयोग एवं ऊर्जा दक्षता पर एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए।

5. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 और 26 जून 2010 को टोरंटो का दौरा किया तथा उस समय 27 जून को एक द्विपक्षीय घटक भी शामिल किया गया। असैन्य परमाणु सहयोग पर करार तथा खनन, संस्कृति एवं उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए तीन एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए।

6. प्रधानमंत्री हार्पर ने पुन: 4 से 9 नवंबर 2012 के दौरान भारत का दौरा किया तथा इस दौरान वह आगरा, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और बंगलौर भी गए। तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए - सामाजिक सुरक्षा करार (दोनों देशों की पेंशन प्रणाली को आपस में जोड़ने तथा पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए), सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स पर एम ओ यू (आई सी टी एवं ई सेक्टर में सहयोग की एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए) और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए डी आर डी ओ तथा योर्क विश्वविद्यालय के बीच एम ओ यू। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों

में सहयोग के लिए भारत - कनाडा करार को क्रियाशील बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए वार्ता को भी अंजाम पर पहुंचाया गया।

7. यात्रा के दौरा जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्री सामरिक स्तर पर द्विपक्षीय भागीदारी को गहन करके और आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संपूरकताओं का बेहतर ढंग से उपयोग करके एक अग्रदर्शी संबंध निर्मित करने की अनिवार्यता पर सहमत हुए। वे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक वार्षिक सामरिक वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

8. विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश मंत्री जान बेयर्ड की सह-अध्यक्षता में पहली सामरिक वार्ता का आयोजन 23 सितंबर 2013 को टोरंटो में हुआ। यह वार्ता सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घावधिक सामरिक दिशा प्रदान करने के लिए सबसे प्रमुख तंत्र है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री बेयर्ड की सह-अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में दूसरी सामरिक वार्ता आयोजित की गई। विदेश मंत्री बेयर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ईद फास्ट भी आए थे तथा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।

9. गवर्नर जनरल डेविड जानसन ने 22 फरवरी से 2 मार्च 2014 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया तथा इस दौरान वह नई दिल्ली, बंगलौर और मुंबई गए। इस यात्रा के दौरान तीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया गए : कनाडा आडियो - विजुअल सह उत्पादन करार; स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा के बीच सहयोग के लिए सहयोग कार्यक्रम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और एसोसिएशन आफ कनाडियन कम्युनिटी कालेज (ए सी सी सी) के बीच एम ओ यू।

10. प्रधानमंत्री मोदी ने 42 साल के अंतराल के बाद 14 से 16 अप्रैल 2015 के दौरान कनाडा का अकेले द्विपक्षीय दौरा किया तथा इस दौरान वह ओटावा, टोरंटो एवं वैंकुवर गए। उन्होंने कनाडा के राजनीतिक, कारोबारी एवं शैक्षिक नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की और 15 अप्रैल को टोरंटो में कोई 10,000 पी आई ओ तथा भारत के दोस्तों को संबोधित भी किया। अन्य बातों के साथ उन्होंने गवर्नर लनरल जानसन से मुलाकात की, प्रधानमंत्री हार्पर के साथ बातचीत की और लिबरल पार्टी के तत्कालीन नेता जस्टिन ड्रुडिव के साथ अच्छी तरह से विचारों का आदान प्रदान किया।

11. इस यात्रा के दौरान जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो तथा कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एम ओ यू; रेल परिवहन में तकनीकी सहयोग के लिए रेल मंत्रालय तथा कनाडा के परिवहन विभाग के बीच एम ओ यू;

नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग को गहन करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय तथा कनाडा के परिवहन विभाग के बीच एम ओ यू; बीमारी के उन्मूलन तथा सेविंग ब्रेन पहल में सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा के बीच मंशा पत्र। भारत को यूरेनियम की दीर्घावधिक आपूर्ति के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के केमको के बीच एक करार पर भी निर्णय लिया गया (दिसंबर 2015 में पहली खेप भारत पहुंची)।

12. दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को एक सामरिक साझेदारी के रूप में स्तरोन्नत करने और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं निवेश, असैन्य परमाणु सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं अंतरिक्ष, संस्कृति, जन दर जन संपर्क तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए। संयुक्त प्रेसवार्ता में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता के हर क्षेत्र में कनाडा के सहयोग एवं निवेश की मांग की - ऊर्जा एवं अवसंरचना, विनिर्माण एवं कौशल, स्मार्ट शहर तथा कृषि उद्योग तथा अनुसंधान एवं शिक्षा। कनाडा के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रानिक टूरिस्ट वीजा (ई टी वी) और 10 वर्षीय वीजा की घोषणा की गई (अब ये दोनों ही लागू हो गए हैं)।

13. 21 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर उनको बधाई देने के लिए श्री जस्टिन ड्रुडिव को फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्दी से जल्दी भारत का आधिकारिक दौरा करने के लिए उनको आमंत्रित किया।

व्यापार एवं अर्थव्यवस्था

14. दो तरफा व्यापार 2010 में 4.2 बिलियन कनाडियन डालर से बढ़कर 2014 में 6.4 बिलियन कनाडियन डालर हो गया है परंतु यह सही क्षमता को नहीं दर्शाता है। कनाडा के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 0.6 प्रतिशत है। भारत की ओर से कनाडा को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से रत्न, आभूषण तथा बहुमूल्य पत्थर, फार्मास्युटिकल उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, जैविक रसायन, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा एवं इस्पात की वस्तुएं आदि शामिल हैं। भारत कनाडा से जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें मुख्य रूप से दलहन, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, एजबेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, कापर, खनिज तथा औद्योगिक रसायन आदि शामिल हैं।

15. कनाडा की सांख्यिकी के अनुसार 2014 में संचयी भारतीय एफ डी आई 3973 मिलियन कनाडियन डालर था जबकि भारत में कनाडा का एफ डी आई 1128 मिलियन कनाडियन डालर था। भारतीय कंपनियों ने विशेष रूप से आई टी, साफ्टवेयर, स्टील तथा प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्रों में

निवेश किया है। कनाडा में महत्वपूर्ण प्रचालनों के तहत आदित्य बिड़ला ग्रुप, एस्सार स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टी मिनरल कनाडा, टेक महिंद्रा, विप्रो, इनफोसिस टेक्नोलाजी, जुबिलांट लाइफ साइंस, एबेलोन एनर्जी इंक, इफको एवं गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जी एस एफ सी) शामिल हैं। दो बैंकों - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आई सी आई सी आई की कनाडा में क्रमश: 7 और 9 शाखाएं हैं।

16. कनाडा की कंपनियां विद्युत एवं ऊर्जा, उपकरण एवं सेवा; तेल एवं गैस; पर्यावरण उत्पाद एवं सेवा; दूर संचार एवं आई टी तथा वित्तीय क्षेत्र एवं बीमा जैसे क्षेत्रों में भारत में सक्रिय हैं। परामर्श एवं इंजीनियरिंग जैसे परंपरागत क्षेत्रों में कनाडा की स्थिति बहुत मजबूत है तथा शिक्षा, साफ्टवेयर विकास तथा वित्तीय सेवा जैसे क्षेत्रों में भी इसकी स्थिति मजबूत है। भारत में प्रचालन करने वाली कनाडा की कंपनियों में एस एन सी लावालिन, बाम्बार्डियर, सी ए ई इंक, सी पी पी आई बी, फेयरफैक्स फाइनेंसियल, ब्रुकफील्ड, सन लाइफ फाइनेंसियल, एक्सपोर्ट डवलपमेंट कनाडा, कैनपोटेक्स लिमिटेड, सी जी आई मोन्ट्रियल, एपोटेक्स इंक, मैककेन फूड लिमिटेड, हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम लिमिटेड, एमडोक्स, एवं बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया शामिल हैं।

17. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने दो तरफा व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता रेखांकित की ताकि पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। वे इस संबंध में विशिष्ट उपायों को लागू करने के लिए सहमत हुए जिसमें द्विपक्षीय विदेशी निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बी आई पी पी ए) को जल्दी से अंतिम रूप देना शामिल है।

18. दोनों नेताओं ने एक प्रगतिशील, संतुलित एवं परस्पर लाभप्रद सी ई पी ए पर जल्दी से निर्णय लेने लिए एक रोडमैप पर सहमति का भी स्वागत किया। सी ई पी ए वार्ता नवंबर 2010 में आरंभ हुई। 9वें चक्र की वार्ता का आयोजन मार्च 2015 में नई दिल्ली में हुआ।

19. भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानिक तंत्रों की भी स्थापना की है जिसमें व्यापार एवं निवेश पर मंत्रालय स्तरीय वार्ता; अपर सचिव, वाणिज्य विभाग के स्तर पर व्यापार नीति परामर्श; और आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र नीति वार्ता शामिल हैं।

20. द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए 2013 में भारत - कनाडा सी ई ओ मंच का गठन किया गया। इस मंच की पहली बैठक नवंबर 2013 में नई दिल्ली में हुई। इस मंच के लिए सचिवालय भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और कनाडियन काउंसिल ऑफ चीफ एग्जिक्यूटिव (सी सी सी

ई) द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस मंच ने प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों, अवसंरचना, शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाओं की पहचान की है।

विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

21. **परमाणु ऊर्जा :** परमाणु सहयोग करार (एन सी ए), जिस पर जून 2010 में हस्ताक्षर किए गए, सितंबर 2013 में लागू हुआ। परमाणु सहयोग करार के लिए उपयुक्त व्यवस्था (ए ए) पर हस्ताक्षर मार्च 2013 में किए गए जिसके तहत असैन्य परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 29 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई। इसकी दूसरी बैठक नवंबर 2014 में ओटावा में हुई। 15 अप्रैल 2015 को परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगले 5 वर्षों में 7 मिलियन पाउंड यूरेनियम कनसंट्रेट की खरीद के लिए सस्काटून आधारित कंपनी कैमको के साथ 350 मिलियन डालर की संविदा पर हस्ताक्षर किया। दिसंबर 2015 में भारत में पहली खेप पहुंची।

22. **ऊर्जा क्षेत्र :** संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध कनाडा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के प्रयासों में एक विश्वसनीय साझेदार बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। नवंबर 2012 में प्रधानमंत्री हार्पर की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय के स्तर पर एक ऊर्जा वार्ता स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे। वार्ता के पहले चक्र का आयोजन अक्टूबर 2013 में ओटावा में हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता उपाध्यक्ष तथा मंत्री जो ओलिवर द्वारा की गई। टी ओ आर के अनुसार ऊर्जा वार्ता के तीन प्रमुख स्तंभ होंगे : हाइड्रोकार्बन, कोयला और विद्युत तथा अन्य ऊर्जा बाजार। अब ऊर्जा वार्ता का पुनर्गठन किया गया है तथा भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को इसका सह अध्यक्ष बनाया गया है। ऊर्जा वार्ता की दूसरी बैठक 5 जुलाई को कैगलरी में हुई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ग्रेग रिकफोर्ड द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई।

23. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच पी एन जी सहयोग पर एक एम ओ यू पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा अल्बर्टा मार्केटिंग पेट्रोलियम कमीशन (ए पी एम सी) और इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के बीच सहयोग पर एक मंशा अभिव्यक्ति पर भी हस्ताक्षर किए गए जिससे संविदा की शर्तों के अधीन आई ओ सी को ए पी एम सी द्वारा क्रूड की बिक्री की संभावनाओं का पता लगाने की रूपरेखा का सृजन हुआ। जनवरी 2014 में इंडियन आयल कारपोरेशन ने कनाडा से 1 मिलियन बैरल परंपरागत क्रूड आयल के स्पाट कार्गो का क्रय किया। इसके बाद इंडियन आयल कारपोरेशन ने अपनी दो सहायक कंपनियों - प्रोग्रेस एनर्जी और पैसिफिक नार्थ वेस्ट एल एन जी (पी एन डब्ल्यू एन एन जी) के माध्यम पेट्रोनस एल एन जी परियोजना में 10 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया।

24. **शिक्षा क्षेत्र :** शिक्षा भारत और कनाडा के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए एम ओ यू पर हस्ताक्षर जून 2010 में किए गए जिसके तहत अन्य बातों के साथ छात्रों एवं संकाय सदस्यों का आदान प्रदान, अनुसंधान एवं पाठ्यचर्या विकास, कार्यशाला एवं सेमिनारों का आयोजन, उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच जुड़वा संबंधों की स्थापना, शैक्षिक अर्हताओं की परस्पर मान्यता को सुगम बनाना, परस्पर हित के क्षेत्रों में नीति वार्ता शामिल है। इस एम ओ यू के तहत गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक अप्रैल 2013 में नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और कनाडा की ओर से डी एफ ए टी डी के एसोसिएट सहायक उप मंत्री द्वारा की गई।

25. कनाडा का एक अच्छी तरह विकसित माध्यमिक पश्चात व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम है जिसके अगुआ सामुदायिक कालेज हैं तथा उनके अनुभव ऐसे सहयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं जिससे कौशल विकास संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान कृषि, परिधान एवं वस्त्र, आटोमोटिव, विमानन, निर्माण, हरित अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखरेख, हाइड्रोकार्बन, आई टी, दूर संचार एवं इलेक्ट्रानिक, खेल तथा जल जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) ने कालेज एण्ड इंस्टीट्यूट कनाडा (सी आई सी) और उसके 10 सदस्यों के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए। सी आई सी और एन एस डी से के बीच एम ओ यू से कार्यबल की आयोजना एवं विकास में मदद मिलेगी तथा यह भारत की कौशल विकास प्रणाली की क्षमता संबंधी विशिष्ट खामियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने में परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगा। संघ अपने सदस्यों तथा भारतीय माध्यमिक पश्चात संस्थाओं के बीच साझेदारी को भी सुगम बनाएगा।

26. **कृषि क्षेत्र :** कनाडा दालों एवं पोटाश का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कोल्ड चैन प्रबंधन, पशुपालन, शुष्क भूमि पर खेती, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तथा कृषि की संपोषणीयता द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्र हैं। 2009 में कृषि सहयोग के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया गया तथा एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया गया जिससे उभरती प्रौद्योगिकी, पशुपालन विकास और कृषि विपणन में ज्ञान के आदान प्रदान पर तीन उप समूहों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों पक्ष सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी मुद्दों पर विज्ञान आधारित चर्चा को सुगम बनाकर पादप, पादप उत्पाद तथा अन्य विनियमित वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहयोग पर एम ओ यू के एक उप समूह के रूप में पादप स्वास्थ्य तकनीकी कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए हैं। भारत के बंदरगाहों पर पहुंचने पर धूम्रीकरण की समस्या का दीर्घावधिक समाधान ढूंढने के लिए दालों के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया गया है। वैश्विक स्तर पर भारत

पोटाश का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है तथा उर्वरकों में प्रयोग के लिए भारत की पोटाश की 25 प्रतिशत आवश्यकता कनाडा से पूरी होती है।

27. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :** 2005 में भारत - कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया। भारत - कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के माध्यम से परामर्शों का नियमित रूप से आयोजन हुआ है। पिछली बैठक जून 2015 में ओटावा में हुई थी। संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए भारत - कनाडा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग (आई सी आर डी) का गठन 2007 में किया गया। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेटिव एण्ड टेक्नोलाजिकल एलायंस - जी आई टी ए (यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे सी आई आई एवं डी एस टी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमोट किया गया है) और कनाडा की ओर से इंटरनेशनल साइंस एवं टेक्नोलाजी पार्टनरशिप कनाडा - आई एस टी पी (यह एक गैर सरकारी संगठन है) आई सी आर डी की संयुक्त परियोजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वयन में लिप्त हैं। जी आई टी ए - आई एस टी पी कनाडा प्लेटफार्म ने उद्योग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि वैकल्पिक ऊर्जा एवं संपोषणीय पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी; जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य अनुसंधान एवं चिकित्सा डिवाइस; पृथ्वी विज्ञान एवं आपदा प्रबंधन; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी); और नैनो प्रौद्योगिकी में अनेक द्विपक्षीय परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

28. आई सी - आई एम पी ए सी टी एस (सामुदायिक परिवर्तन एवं संपोषणीयता की गति तेज करने के लिए नवाचारी बहुविषयक साझेदारी के लिए भारत - कनाडा केन्द्र), जो भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान सहयोग के विकास के लिए समर्पित एक कनाडा - भारत उत्कृष्टता अनुसंधान केन्द्र है, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं, उद्योग नवाचारकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं, सरकारी एजेंसियों एवं सामुदायिक संगठनों को समुदायों के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। आई सी - आई एम पी ए सी टी एस गंगा नदी को साफ करने के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी समाधान ढूंढने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ काम कर रहा है; सुरक्षित एवं संपोषणीय अवसंरचना तथा समेकित जल प्रबंधन जैसी पहलों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा डी एस टी के साथ 'स्वास्थ्य के लिए जल' साझेदारी में काम कर रहा है।

29. **बाहरी अंतरिक्ष :** भारत और कनाडा अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी प्रेक्षण, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं तथा अंतरिक्ष मिशनों के लिए बुनियादी सहायता के क्षेत्रों में 1990 के दशक से आपस में सहयोग कर रहे हैं। बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोग तथा विशेष रूप से उपग्रह ट्रैकिंग एवं स्पेस एस्ट्रोनामी के क्षेत्र में दो कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो और सी एस ए (कनाडियाई अंतरिक्ष एजेंसी) ने एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं। उपग्रह ट्रैकिंग प्रचालन के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिसंबर 2003 में हस्ताक्षरित कार्यान्वयन व्यवस्था के तहत इसरो और सी एस ए ने अपने अपने

टेलीमेट्री एवं ट्रैकिंग कमांड (टी टी सी) स्टेशनों की सेवाओं को साझा किया है। दोनों एजेंसियां एक अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (यू वी आई टी) के निर्माण पर साथ मिलकर काम कर रही हैं जिसे भारत के मल्टी वेव लेंथ एस्ट्रोनामिकल सेटलाइट एस्ट्रोसैट में प्रवाहित किया जाएगा, जिसे 2015 में लांच किए जाने की उम्मीद है।

30. कनाडा के साथ भारत के मजबूत वाणिज्यिक संबंध भी हैं। अंतरिक्ष, जो इसरो का वाणिज्यिक प्रकोष्ठ है, ने टोरंटो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एरो स्टेट स्टडी (यू टी आई ए एस) के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत नौ नैनों उपग्रह लांच किया है। अंतरिक्ष ने फरवरी 2013 में पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (पी एस एल वी - सी 20) पर सहायक उपग्रहों के रूप में एक माइक्रो सेटलाइट सेफायर (मैक डोनाल्ड, डेटविलर एण्ड एसोसिएट, एम डी ए के साथ वाणिज्यिक संविदा), कनाडा और नियोसैट (माइक्रोसैट सिस्टम, कनाडा के साथ संविदा) भी लांच किया है। पी एस एल वी - सी 23 जिसे जून 2014 में लांच किया गया, पर कनाडा के दो उपग्रह - कैनेक्स 4 और कैनेक्स 5 हैं जो टोरंटो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फार एरो स्टेट स्टडी के स्पेस फ्लाइट लैबोरेटरी से हैं।

भारतीय समुदाय :

31. कनाडा में भारतीय मूल के 1.2 मिलियन से अधिक व्यक्ति रहते हैं। भारत की ओर से कनाडा में पहला पलायन 1897 में कनाडा के पश्चिमी तट पर हुआ जब रेलवे निर्माण के लिए पंजाब से लंबर वर्कर और मजदूर वहां पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारतीयों का पलायन पूर्वी तट की ओर शिफ्ट हुआ। कनाडा में उत्प्रवासन की दूसरी प्रमुख लहर 1970 के दशक से पूर्वार्द्ध में शुरू हुई। 1967 प्वाइंट सिस्टम ने कनाडा में भारतीय डायसपोरा की प्रोफाइल के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्वाइंट सिस्टम के कारण पेशा के अनुसार प्रवासियों का चयन किया गया जिसने डाक्टरों, इंजीनियरों एवं शिक्षाविदों को कनाडा की ओर आकर्षित किया। आज लगभग 90 प्रतिशत समुदाय टोरंटो, बैंकुवर एवं मांट्रियल के महानगरीय क्षेत्रों में तथा अन्य प्रमुख शहरों जैसे कि ओटावा, कैगलरी, विनीपेग, एडमोंटन, वाटरलू और हैलीफैक्स में रह रहा है। ग्रेटर टोरंटो एरिया (जी टी ए) में सबसे अधिक भारतीय समुदाय है जिसकी अनुमानित संख्या 650,000 के आसपास है जिसके बाद बैंकुवर का स्थान है जहां लगभग 300,000 भारतीय समुदाय रहता है। अनुमान है कि दो तिहाई भारतीय कनाडियन पंजाबी भाषी हैं, जिसके बाद उनका स्थान है जो गुजराती बोलते हैं। भारतीय समुदाय सांस्कृतिक दृष्टि से सक्रिय है तथा उन्होंने अपने आपको विभिन्न संगठनों में संगठित किया है।

32. अनेक भारतीय कनाडियन व्यवसायी उद्यमों, सरकारी सेवाओं एवं अन्य पेशों में प्रमुख पदों पर हैं। संघीय संसद तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भी डायसपोरा का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। वर्तमान हाउस ऑफ कामंस (जिसके लिए चुनाव 19 अक्टूबर 2015 को हुए थे), में भारतीय मूल के सांसदों की संख्या 19 है (पहले इनकी संख्या 9 थी)। आज चार पी आई ओ कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं (पिछले मंत्रिमंडल

में दो राज्य मंत्री थे)। महत्वपूर्ण भारत - कनाडा संगठनों में शामिल हैं - भारत - कनाडा व्यापार परिषद (सी आई बी सी), भारत - कनाडा प्रतिष्ठान (सी आई एफ), भारत - कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स (आई - सी सी सी) और अन्य स्थायीन चैंबर एवं संघ।

33. **सांस्कृतिक सहयोग** कनाडा में भारी मात्रा में भारतीय समुदाय को देखते हुए ऐसे अनेक स्थानीय संगठन हैं जो भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से अभिनय कलाओं को बढ़ावा देते हैं। आई सी सी आर के साथ मिलकर भारतीय मिशन इन सांस्कृतिक संगठनों की गतिविधियों को संपूरित करने का प्रयास करता है। तीन साल की अवधि के लिए जून 2010 में कनाडा के विरासत विभाग तथा भारत के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए। एम ओ यू जो दिसंबर 2013 में कालातीत हो गया है, नवीकरण के लिए वार्ता के अधीन है तथा 2017 में भारत में कनाडा वर्ष का आयोजन करने के लिए कनाडा के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, ओटावा की वेबसाइट
http://www.hciottawa.ca

*****

दिसंबर, 2015